

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 57/23

GCMS NO 2023/163



1. प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुशतला हाल निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) रूपचन्द्र पुत्र बदरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुशतला हाल निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) जरिये मुख्तार आम प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गुढियारी रायपुर सुरेश चंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुशतला हाल निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) जरिये मुख्तार आम प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गुढियारी रायपुर(मृतक)
- 3/1. शिवानी शर्मा पत्नि सुरेश चंद
- 3/2. विकास शर्मा पुत्र सुरेश चंद
- 3/3. वैभव शर्मा पुत्र सुरेश चंद
- 3/4. शीतल शर्मा पुत्री सुरेश चंद
- 3/5. सोनल शर्मा पुत्री सुरेश चंद संमस्त जातियान ब्राह्मण निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) जरिये मुख्तार आम प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गुढियारी रायपुर
4. महेश चन्द पुत्र बदरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुशतला हाल निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) जरिये मुख्तार आम प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गुढियारी रायपुर
5. रमेश चंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुशतला हाल हाल निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) जरिये मुख्तार आम प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गुढियारी रायपुर
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र बलभद्र जाति ब्राह्मण निवासी 18बाल मंदिर कालोनी सवाई माधोपुर
7. श्रीमती मीना शर्मा पत्नि गोकलेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम कुशतला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
8. शैलेन्द्र कुमार पुत्र चन्द्रशेखर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुशतला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सीमा गर्ग पत्नि डॉक्टर पवन गर्ग जाति महाजन निवासी खत्री का बाग रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पो०

(अपील विरुद्ध मु०नं० 149/19 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर)  
अभिभाषक अपीला० श्री श्रीदास सिंह  
अभिभाषक रेस्पो० श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

दिनांक 18.6.2025



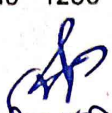
निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर



प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.1.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादिया/रेस्पोंड संख्या द्वारा वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 सपटित धारा 92 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम कुशतला तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित आराजीयात ख० न० 250, 294, 295, 297, 363, 374, 376, 1013, 1014, 1236, 1245 / 5669, 1246, 1247, 1248, 1251 / 5484, 4944 कुल किता 16 कुल रकबा 7.29 है० स्थित है। जिसमें वादिया 1/3 भाग की रिकार्डेड सहखातेदार है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। वादियां एवं प्रतिवादीगण 1 ता 8 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में वादिया का 1/3 भाग है जो कि वादिया ने पूर्व सहखातेदार राजेन्द्र प्रसाद एवं विजेन्द्र प्रसाद पिसरान बल्लभ प्रसाद जाति ब्राह्मण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। प्रतिवादी न० 6 नरेन्द्र कुमार का उक्त आराजीयात में 1/2 भाग है। प्रतिवादी संख्या 7 मीना का खसरा न० 250 रकबा 1.33 है० में 5/12 भाग जो कि यह भाग श्रीमती मीना द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। खसरा न० 295 रकबा 0.52 है० में भी प्रतिवादियां मीना शर्मा का भाग 1159/5200 है जो कि यह भाग उसने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था। प्रतिवादी न० 8 शलेन्द्र शर्मा का खसरा न० 295 रकबा 0.52 है० में 1007/5200 भाग है जो कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। उसी प्रकार ख० न० 294 व 297 कुल रकबा 0.93 है० में भी प्रतिवादी शलेन्द्र शर्मा का भाग 5/12 है जो कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। खसरा न० 4944 रकबा 0.86 है० में शलेन्द्र का भाग 17/86 है जो कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का भाग खसरा न० 250, 295, 294 व 297 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अपना सम्पूर्ण 5/12 भाग उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 को विक्रय कर दिया गया है तथा खसरा न० 4944 में भी उनके द्वारा 17/86 भाग प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय कर दिया है जिस कारण उक्त आराजीयात खसरा न० 250, 295, 297 व 4944 को छोड़कर शेष आराजीयात ख० न० 363, 374, 376, 1013, 1014, 1236, 1245 / 5669, 1246, 1247, 1248, 1251 / 5484 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का भाग 5/12 है तथा खसरा न० 4944 रकबा 0.86 है० में इनके द्वारा विक्रय किये गये 17/86 भाग को छोड़कर बचा हुआ शेष भाग। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के अलावा सहखातेदार श्रीमती आन्नदी पत्नि स्व० बदरी लाल ब्राह्मण का उक्त समस्त आराजीयात में 1/12 भाग रहा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिस प्रतिवादी न० 1 लगायत 5 है। जो अपनी माता मृतक आन्नदी के स्थान पर 1/12 भाग के अधिकारी है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का उपरोक्त क्र.स. 5 में बताये अनुसार स्वयं के भाग के अलावा उनके हिस्से में अपनी माता का भी 1/12 भाग है। वादिया एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 ने उक्त समस्त आराजीयात का अपने भाग के अनुसार पारस्परिक सहमति से मौके पर मौखिक रूप से बंटवारा कर रखा है तथा बंटवारे अनुसार ही वादिया एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने अपने भाग पर काबिज चले आये है, जिसके अनुसार वादिया के हिस्से में ख० न० 1236 रकबा 0.28 है०, 1246 रकबा 0.30 है०,

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर



1245/5669 गैर मुमकिन चाह रकबा 0.01 है0, 1247 रकबा 0.16 है0, 1248 रकबा 0.68 है0, 1014 रकबा 0.18 है0, 1013 रकबा 0.20 है0, 295 रकबा 0.52 है0 होने से वादिया मौके पर इन पर काबिज चली आई है उसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 भी अपने अपने हिस्से में आये भाग पर मौके पर काबिज चले आये है। गैर मुमकिन चाह में पानी की मात्रा न्यून होने के कारण वादिया ने अपने भाग में नवीन बोरिंग भी लगवा ली है। पक्षकारान के मध्य मौके पर तो मौखिक बंटवारा हो रहा है लेकिन विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण वादिया एवं प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खातेदारी दर्ज नहीं हुई है। राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। वादिया ने प्रतिवादीगण से विधिवत बंटवारा कराने के लिए कहा तो उनके द्वारा इंकार तो नहीं किया गया परन्तु टालमटोल करते रहे कि सब अपने अपने भाग पर काबिज है इसलिए जल्दी क्या है बाद में कभी करवा लेगे। लेकिन वादिया द्वारा दिनांक 10.10.19 को बंटवारे के लिए पुनः कहा तो उनके द्वारा इंकार कर दिया गया और कहा कि हम आगे होकर न्यायालय या तहसील में जाकर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तुम्हें जल्दी हो तो तुम जाकर कार्यवाही करो। प्रतिवादीगण को विधिवत बंटवारा कराने से इंकार करने का कोई अधिकार नहीं है। वादिया एवं प्रतिवादीगण के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं हो इस कारण विधिवत बंटवारा कराया जाना आवश्यक है। वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा प्रतिवादीगण उत्पन्न नहीं करे इसलिए उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक है। अतः ग्राम कुशतला तहसील सवाई माधोपुर की वाद पत्र में वर्णित कुल आराजीयात कुल कित्ता 16 कुल रकबा 7.29 है0 का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज भाग के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर पक्षकारों के मध्य पारस्परिक सहमति से पूर्व से चले आ रहे मौखिक विभाजन व कब्जे के अनुसार ख0न0 1236 रकबा 0.28 है0, 1246 रकबा 0.30 है0, 1245/5669 गैर मुमकिन चाह रकबा 0.01 है0, 1247 रकबा 0.16 है0, 1248 रकबा 0.68 है0, 1014 रकबा 0.18 है0, 1013 रकबा 0.20 है0, 295 रकबा 0.52 है0 वादिया को दिया जावे तथा उसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को भी मौखिक व कब्जे के अनुसार ही विभाजन में भूमि दी जावे। विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नक्शा ट्रेस में इन्द्राजात किये जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादिया/रेस्प0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया/रेस्प0 संख्या 1 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम कुशतला में मौके पर बाहमी बंटवारा कर समस्त खातेदारान अपने अपने हिस्से को अलग अलग काश्त करते चले आ रहे हैं। रेस्प0 संख्या 1 द्वारा आराजीयात का तकासमा का दावा प्रस्तुत किया गया था जिसका कोई नोटिस अपीलार्थीगण को प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा प्रारंभिक तकासमा डिक्री जारी की गई। यदि अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर



न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करते तो यह निर्णय कदापि नहीं होता इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। मुकदमा में प्राथमिक डिक्री बनाये जाने के बाद रेस्पों नं० 2 द्वारा तकासमा स्कीम बनाई गई उसका भी अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया। तकासमा स्कीम मौके पर नहीं बनाई गई अर्थात् रेस्पों संख्या 1 की उपस्थिति में सिविल कार्यालय में बैठकर बनाई गई है। यदि तकासमा स्कीम मौके पर बनाई जाती व सुनवाई का मौका दिया जाता तो आराजीयात पर वर्तमान कब्जे की स्थिति स्पष्ट हो जाती तो विवादित निर्णय व डिक्री कदापि जारी नहीं होते इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। रेस्पों संख्या 2 द्वारा तकासमा स्कीम प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिक डिक्री जारी किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया। यदि अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐतराज प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस अपीलार्थीगण को दिया जाता तो अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करते तो यह निर्णय कभी नहीं होता। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। टीनेन्सी एक्ट में तकासमा किये जाने हेतु नियम बनाये गये हैं, नियम 20 में स्पष्ट प्रावधान है कि सहखातेदारों के मौके पर आराजीयात के कब्जे के अनुसार यथा सम्भव तकासमा किया जावेगा, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 20 की पालना नहीं की गई है। इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 53 आर टी एक्ट के तहत कृषि जोत का विभाजन करने के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 6.11.04 को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अनुसार प्रत्येक काश्तकार को विभाजन में मिलने वाली भूमि पर रास्ते का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विभाग के इस आदेश की पालना नहीं की गई। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण 1 लगायत 5 की मां का देहान्त 25 वर्ष पूर्व दिनांक 30.11.99 को हो चुका है तथा वह मौके पर किसी आराजी को काश्त नहीं करती है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृत काश्तकार आन्नदी पत्नि बदरीलाल का भी तकासमा कर उसके नाम अलग से खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी ख० नं० 1248 रकबा 0.68 है० में अपीलार्थी नं० 6 का पिछले 6-7 वर्षों से अमरूदों का बगीचा लगा हुआ है जिसमें अमरूदों के बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं तथा चारों तरफ तारबंदी हो रही है। तकासमा में यह खसरा नं० 1248 रेस्पों नं० 1 को दिया गया है। जो विधि विरुद्ध है। आराजी ख० नं० 294/1,295/1,297/1 अपीलार्थीगण नं० 1 लगायत 5 के कब्जे काश्त में है जिनको तकासमा में रेस्पों संख्या 1 को दिया गया है जो गलत है। आराजी ख० नं० 250 रकबा 1.33 है० अपीलार्थीगण नं० 7 व 8 के कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके टुकड़े कर दिये गये हैं। जबकि काश्तकार अपने हिस्सानुसार पूर्व से ही अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। इसी प्रकार आराजी ख० नं० 363 रकबा 0.18 है०, 374 रकबा 0.72 है०, 376 रकबा 0.67 है०, 4944 रकबा 0.86 है० पर कब्जा काश्त रेस्पों नं० 1 का है परन्तु तकासमा में यह नम्बर अपीलार्थी नं० 1 लगायत 5 व 7 तथा 8 को दिये गये हैं जो कब्जे काश्त के विपरीत है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण एवं रेस्पों नं० 1 ने पूर्व में ही सम्पूर्ण आराजीयात के रकबे का अपने हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर



अनुसार बंटवारा कर रखा है तथा मौके पर प्रत्येक खातेदार ने अपनी अपनी आराजी की तारबंदी करवा रखी है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय व डिक्री से पक्षकारान के मध्य एक नया विवाद खडा हो गया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय होने से अपीलार्थीगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। दिनांक 2.8.23 को हल्का पटवारी द्वारा बताये जाने पर जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी के अनुसार अपील अन्दर मियाद पेश है परन्तु देरी के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण की सुनवाई कर तकासमा किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

रेस्पो० के अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात कुल कित्ता 16 कुल रकबा 7.29 है० में से वादिया/रेस्पो० संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के सहखातेदार राजेन्द्र प्रसाद, विजेन्द्र प्रसाद पुत्रान बलभद्र प्रसाद शर्मा के हिस्से 1/3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.5.19 को खरीद की गई है। विक्रय पत्र के आधार पर नामा० संख्या 3453 दिनांक 24.6.19 के आधार पर जमाबंदी में इन्द्राज होने के कारण वादिया/रेस्पो० संख्या 1 खाता संख्या 427 में अंकित भूमि में 1/3 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार हुई है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। चूंकि विवादित आराजीयात का वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवारा होने से पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। परन्तु विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण ही वादिया/रेस्पो० को विधिवत बंटवारा कराने का अधिकार प्राप्त होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय में तकासमा का वाद पेश किया गया था। अपीलांत का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी बिना तामिल के ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया है परन्तु प्रतिवादीगण बाबजूद तामिल उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वादिया/रेस्पो० साक्ष्य ली जाकर तहसीलदार संवाई माधोपुर से मौके एवं कब्जे के अनुसार प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर विधिवत रूप से तकासमा किया गया है। तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार की गई है जिसमें रेस्पो० के अलावा गांव के अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं तथा तकासमा स्कीम पर स्पष्ट नोट अंकित है कि प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के मौके पर उपस्थित नहीं है। तकासमा स्कीम मौके पर तैयार की जाकर सरेआम सुनाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम कुशतला तहसील संवाई माधोपुर के खाता संख्या 427 में दर्ज कुल कित्ता 16 कुल रकबा 7.29 है० में वादिया एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जो पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी से स्पष्ट है। वादिया/रेस्पो० संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के सहखातेदार राजेन्द्र प्रसाद, विजेन्द्र प्रसाद पुत्रान बलभद्र प्रसाद के हिस्से की 1/3 आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
संवाई माधोपुर



पत्र दिनांक 8.5.19 को क्रय किया गया है जिसका नामा संख्या 3453 दिनांक 24.6.19 को रेस्पो0 न0 1 के नाम तस्दीक होने से राजस्व रिकार्ड में बंतौर सहखातेदार दर्ज हुआ है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है एवं वह उसका बंटवारा कराने का अधिकार रखता है। वादिया/रेस्पो0 न0 1 द्वारा इसी परिपेक्ष्य में विवादित आराजीयात का बंटवारा कराये जाने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय से की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब तो किया गया परन्तु उनको रजिस्टर्ड सम्मन प्राप्त हुए या नहीं इसके संबंध में डाक विभाग से ट्रेकिंग रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही उनके विरुद्ध दिनांक 2.9.20 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। जबकि विधिक रूप से डाक विभाग से ट्रेकिंग रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लानी चाहिए थी। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा जो तकासमा स्कीम तैयार की गई है उस पर किसी भी प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं ना ही उनको मौके पर किस दिवस को उपस्थित होना है के बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना दिये जाने का कोई प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवारा किया गया है उसमें राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 6.11.04 की पालना नहीं की गई है उक्त परिपत्र में यह दिशा निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रत्येक काश्तकार को विभाजन में मिलने वाली भूमि पर रास्ते का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में रास्ते के बाबत किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एक पक्षीय है। जिसे पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थीगण विवादित आराजीयात के सहखातेदारान हैं जिनका विवादित आराजीयात में हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्ट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0 न0 149/19 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.1.21 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6.11.04 की रोशनी में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.7.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर